उपलब्धि

माइक्रो फाइनेंस एसोसिएशन ऑफ यूपी के अधिवेशन में साझा की गई जानकारी

माइक्रो फाइनेंस का बढ़ा दायरा, गोरखपुर नंबर वन

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। यूपी में माइक्रो फाइनेंस लोगों को तेजी से स्वावलंबी बना रहा है। बेहद छोटे उद्यमियों और व्यापारियों के लिए माइक्रो फाइनेंस कंपनियां बड़ा विकल्प बनकर उभरी हैं। छह महीने में 2020 करोड़ का ऋण देकर गोरखपुर यूपी में नंबर वन है। सोमवार को समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने माइक्रो फाइनेंस एसोसिएशन ऑफ यूपी (उपमा) के सालाना अधिवेशन में रिपोर्ट जारी की।

गोमती नगर स्थित एक होटल में हुए देश की प्रमुख माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के अधिवेशन में असीम अरुण ने कहा कि माइक्रो फाइनेंस महिलाओं के रोजगार में सहायक बनकर उन्हें स्वावलंबी बना रहा है। ये ऐसा विषय है जो राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा कि उपमा ऐसी कार्य योजना बना रहा है जो राज्य के विकास मे सहयोगी होने के साथ दस खरब डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पूरा करने में मददगार होगी।

माइक्रो फाइनेंस विशेषज्ञ विजय महाजन ने बताया कि इसके जरिये राज्य की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन कर बेरोजगारी को दूर करने में किया जा सकता है।

उत्कर्ष बैंक के एमडी गोविंद सिंह ने कहा कि हमारे बैंक के ऋण ग्रामीण या अविकसित इलाकों की महिलाओं या छोटे कारोबारियों के लिए होते हैं। हम इस वर्ग को वित्तीय समृद्धि से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

ये है माइक्रो फाइनेंस : उपमा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर सिन्हा ने बताया कि माइक्रो फाइनेंस जिसे माइक्रो क्रेडिट भी कहा जाता है। यह एक प्रकार की बैंकिंग सेवा है जो कम आय वाले व्यक्तियों या समूहों को दी जाती है। माइक्रो फाइनेंस में ईस्टर्न जोन सबसे आगे है। दूसरे नंबर पर वेस्टर्न जोन और तीसरे पर सेंट्रल जोन है।

माइक्रो फाइनेंस में शीर्ष जिले

जिला	कुल लोन
गोरखपुर	2020 करोड़
महाराजगंज	1587 करोड़
कुशीनगर	1557 करोड़
बिजनौर	1514 करोड़
देवरिया	1502 करोड़
आगरा	1322 करोड़
सहारनपुर	1225 करोड़
प्रयागराज	1073 करोड़
बुलंदशहर	1026 करोड़
मुजफ्फरनगर	989 करोड़

सीडीआर में वृद्धि आर्थिक विकास का संकेत

भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व चेयरमैन दिनेश खारा ने क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो (सीडीआर) को लेकर कहा कि सीडीआर (ऋण जमा अनुपात) को क्रेडिट एब्जॉर्शन कैपेसिटी के रूप में देखा जाना चाहिए। बड़े समूह दिल्ली या मुंबई से लोन लेते हैं। अगर यहां की बैंक शाखाओं में क्रेडिट दिख रहा है तो यह संकेत है कि यूपी में ही पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। यानी सीधे तौर पर विकास होगा। सरकारी योजनाओं में एनपीए को लेकर उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे वित्तीय साक्षरता बढ़ेगी, एनपीए घटता जाएगा। लोन में अनियमितता से सिबिल स्कोर खराब होता है। इससे भविष्य में लोन या किसी भी तरह की वित्तीय मदद में परेशानी आती है। इसे ऋण लेने वाले समझते हैं।